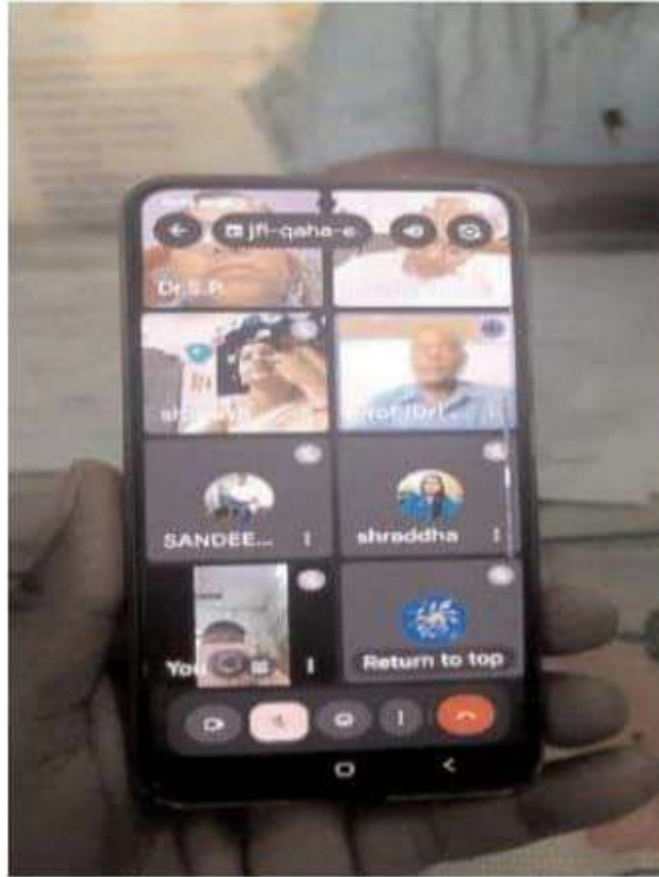


अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिवस का ऑनलाइन सत्र संपन्न

प्रयागराज, 15 अक्टूबर (देवव्रत संवाद)। छात्रों के बहुआयामी विकास में शिक्षा की भूमिकाह्व विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिवस का ऑनलाइन सत्र आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद एवं कुलभास्कर आश्रम पी.जी. कॉलेज, प्रयागराज के सहयोग से किया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की वंदना से हुआ। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का संचालन डॉ. आदेश कुमार वर्मा (आयोजन सचिव) ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. गीतांजलि मौर्य, प्राचार्य, कुलभास्कर आश्रम पी.जी. कॉलेज, प्रयागराज ने की। संयोजक प्रो. पवन के. पचौरी ने संगोष्ठी के उद्देश्य और विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। महाविद्यालय के संरक्षक चौधरी राघवेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कायस्थ पाठशाला, प्रयाग, ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि ह्रुशिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। मुख्य वक्ता (कीनोट स्पीकर) नेपाल से प्रो. दिलीप कुमार झा ने शिक्षा के बहुआयामी स्वरूप पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए।

इसके उपरांत तकनीकी सत्रों में देश-विदेश के शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। कनाडा से इंजीनियर सुशांत दुबे और इटली से इंजीनियर मीतूल बादल ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों



में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

तृतीय तकनीकी सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रीना मुखर्जी ने शिक्षा की बहुआयामी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में संयोजक एवं आयोजन सचिव ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। प्रथम दिवस का ऑनलाइन सत्र अत्यंत सफल एवं

ज्ञानवर्धक रहा, जिसमें देश-विदेश से अनेक शिक्षाविद, शोधार्थी एवं विद्यार्थी सम्मिलित हुए और लगभग देश-विदेश के 30 के शोध पत्रों का वाचन भी हुआ प्रथम दिवस का आभार प्रदर्शन प्रो सी एस चौबे द्वारा किया गया। द्वितीय दिवस का ऑफलाइन सत्र 16 अक्टूबर 2025 को कुलभास्कर आश्रम पी.जी. कॉलेज, प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा।

दो माह से नहीं मिला जननी सुरक्षा योजना का लाभ

अंबेडकरनगर, 15 अक्टूबर (देवव्रत संवाद)। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के बाद मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान पिछले दो माह से ठप पड़ा है। अप्रैल से सितंबर के बीच जिले में हुए 10 हजार प्रसवों में से मात्र 25 प्रतिशत महिलाओं को ही भुगतान हो पाया है। अगस्त से बजट नहीं आने और पोर्टल पर फीडिंग में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह संकट गहराया है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रसूताओं को योजना के तहत 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जानी होती है। नियम के अनुसार यह भुगतान प्रसव के 24 से 48 घंटे के भीतर होना चाहिए, ताकि प्रसूता के पोषण और आवश्यकताओं में कोई बाधा न आए।